



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email: helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai-400001

फोन/Phone: 022- 22660502

6 अगस्त 2021

गवर्नर का वक्तव्य : 6 अगस्त 2021

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 4, 5 और 6 अगस्त 2021 को हुई। उभरती घरेलू और वैश्विक समष्टि आर्थिक तथा वित्तीय स्थितियों एवं संभावनाओं के आकलन के आधार पर, एमपीसी ने नीति रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। एमपीसी ने 5 - 1 के बहुमत से यह भी निर्णय लिया कि यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखा जाए। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है। परिवर्तनीय रेपो दर भी 3.35 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है।

2. आज, हम जून 2021 में एमपीसी की बैठक के समय की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में हैं। महामारी की दूसरी लहर थोड़ी कम हो रही, संरोधन को आसान किया गया है और हम धीरे-धीरे सुधार की ओर वापस आ रहे हैं, बैंकनी निर्माण और प्रशासन लगातार बढ़ रहा है। फिर भी समय की मांग है कि हम अपनी कमर कस कर रखें और खासकर देश के कुछ हिस्सों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तीसरी लहर की किसी भी संभावना के प्रति सतर्क रहें।

3. सरकार के साथ हमारे कार्यों का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली को स्वस्थ और स्थिर रखते हुए तनाव को कम करना और विकास को प्राथमिकता देना है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर¹ के दो उद्धरणों को एक साथ पढ़कर हमारे दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन किया जा सकता है "लेकिन मुझे पता है, किसी तरह, कि केवल जब पर्याप्त अंधेरा हो, तो ही आप सितारों को देख सकते हैं। चलते रहो। कुछ भी आपको धीमा न होने दें। आगे बढ़ो"

4. मैं एमपीसी के निर्णय के पीछे के तर्क को प्रस्तुत करके शुरू करता हूं। एमपीसी ने मुद्रास्फीति लक्ष्य के ऊपरी सहिष्णुता बैंड से ऊपर होने वाले दो हालिया मुद्रास्फीति प्रिंटों के तहत अपनी बैठक की। इसने इस बात पर ध्यान दिया कि आर्थिक गतिविधि जून में एमपीसी की अपेक्षाओं की तर्ज पर व्यापक रूप से विकसित हुई है और अर्थव्यवस्था दूसरी लहर के झटके से उबर रही है। कुछ समय के अंतराल के बाद मानसून फिर से शुरू हो गया है और खरीफ की बुवाई रफ्तार पकड़ रही है। कुछ उच्च आवृत्ति संकेतक भी जून-जुलाई के दौरान फिर से ऊपर दिख रहे हैं। हमारी उम्मीद यह है कि टीकाकरण के प्रगतिशील उन्नयन,

¹ स्रोत: मेम्फिस, टेनेसी में बिशप चार्ल्स मेसन मंदिर (3 अप्रैल 1968) और वाशिंगटन, डीसी यूएसए में स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना तीर्थयात्रा (कॉल टू कॉन्शियस, 1957) में दिए गए भाषण।

निरंतर बृहद नीतिगत समर्थन, निर्यात की अधिकता, कोविड संबंधित प्रोटोकॉल के लिए बेहतर अनुकूलन और सौम्य मौद्रिक और वित्तीय स्थितियों के साथ गतिविधि में तेजी आने की संभावना है।

5. उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति मई में तेजी से बढ़ी, जो प्रतिकूल आपूर्ति झटके, उच्च लॉजिस्टिक लागत, उच्च वैश्विक पण्य कीमतों और घरेलू ईंधन करों के संयोजन को दर्शाती है। जून में, हेडलाइन मुद्रास्फीति ऊपरी सहनशीलता के स्तर से ऊपर रही, लेकिन कीमतों की गति में सौम्यता आई। इसके अलावा, कोर मुद्रास्फीति मई में अपने चरम से सौम्य हुई। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है; ओपेक प्लस करार के परिणामस्वरूप कीमतों में कोई भी कमी मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने में योगदान दे सकती है।

6. संतुलन पर, समग्र मांग की संभावनाओं में सुधार हो रहा है, लेकिन अंतर्निहित स्थितियां अभी भी कमजोर हैं। कुल आपूर्ति भी महामारी-पूर्व के स्तर से नीचे है। जबकि आपूर्ति बाधाओं को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में आपूर्ति-मांग संतुलन को बहाल करने के लिए और सुधार करने की आवश्यकता है। हाल के मुद्रास्फीति दबाव चिंता पैदा कर रहे हैं; लेकिन वर्तमान आकलन यह है कि ये दबाव अस्थायी हैं और बड़े पैमाने पर प्रतिकूल आपूर्ति पक्ष कारकों से प्रेरित हैं। हम महामारी से उत्पन्न एक असाधारण स्थिति के बीच में हैं। महामारी के दौरान मौद्रिक नीति का संचालन अनुकूल वित्तीय स्थितियों को बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है जो संवृद्धि का पोषण और कार्याकल्प करते हैं। इसलिए, इस स्तर पर, सभी पक्षों से निरंतर नीतिगत समर्थन - राजकोषीय, मौद्रिक और क्षेत्रीय - की आवश्यकता है ताकि नवीन और संकोची बहाली को बढ़ावा दिया जा सके। जैसे ही मजबूत और सतत विकास की संभावनाएं सुनिश्चित होती हैं, एमपीसी मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर करने के अपने जनादेश के प्रति सचेत रहती है। तदनुसार, एमपीसी ने मौजूदा रेपो दर को 4 प्रतिशत पर बनाए रखने और अपनी सभी बारीकियों के साथ निभावकारी रुख को जारी रखने का निर्णय लिया।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति का आकलन

घरेलू संवृद्धि

7. वायरस की दूसरी लहर के कम होने और अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने के साथ घरेलू आर्थिक गतिविधियां सामान्य होने लगी हैं। उच्च-आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि (i) खपत (निजी और सरकारी दोनों), (ii) निवेश और (iii) बाह्य मांग, सभी कर्षण प्राप्त करने के मार्ग पर हैं। मुझे इन तीनों पहलुओं में से प्रत्येक के बारे में विस्तार से बताना चाहिए। प्रतिबंधों में ढील और टीकाकरण के बढ़ते कवरेज से यात्रा, पर्यटन और मनोरंजक गतिविधियों सहित वस्तुओं और सेवाओं पर निजी खर्च को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे कुल मांग में व्यापक सुधार होगा। कृषि और ग्रामीण मांग की मजबूत संभावनाएं निजी खपत का समर्थन करना जारी रखेगा। विनिर्माण और गैर-संपर्क गहन सेवाओं में सुधार, रुकी हुई मांग का आरंभ और टीकाकरण की गति के साथ शहरी मांग में तेजी आने की संभावना है। यह कई उच्च आवृत्ति संकेतकों जैसे, ऑटोमोबाइल का पंजीकरण, बिजली की खपत, गैर-तेल गैर-सोने का आयात, उपभोक्ता टिकाऊ बिक्री और शहरी श्रमिकों को काम पर रखना, में गति को प्रोत्साहित करके पुष्टि करता है। रिज़र्व बैंक के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के जुलाई दौर के नतीजे बताते हैं कि एक साल आगे मनोभाव ऐतिहासिक निचले स्तर से आशावादी क्षेत्र में लौट आई है। सूचीबद्ध फर्मों के शुरुआती नतीजे बताते हैं कि कॉरपोरेट्स सूचना प्रौद्योगिकी फर्मों के नेतृत्व में बिक्री, वेतन वृद्धि और लाभप्रदता में अपनी स्वस्थ वृद्धि को बनाए रखने में सक्षम रहे हैं। यह उपभोक्ताओं की कुल प्रयोज्य आय का भी समर्थन करेगा।

8. हालांकि निवेश की मांग अभी भी कमजोर है, क्षमता उपयोग में सुधार, इस्पात की बढ़ती खपत, पूंजीगत वस्तुओं के उच्च आयात, अनुकूल मौद्रिक और वित्तीय स्थिति और केंद्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेजों से लंबे समय से प्रतीक्षित पुनरुद्धार के आरंभ होने की उम्मीद है। रिज़र्व बैंक के सर्वेक्षणों में मतदान करने वाली फर्मों को 2021-22 की दूसरी तिमाही में उत्पादन मात्रा और नए ऑर्डर में विस्तार की उम्मीद है जो कि 2021-22 की चौथी तिमाही तक बनी रहेगी, जो निवेश के लिए अच्छा संकेत है। कारोबारों द्वारा महामारी के दौरान अपनाए गए नवाचार और कार्य मॉडल, महामारी के कम होने के बाद भी दक्षता और उत्पादकता लाभ प्राप्त करना जारी रखेंगे। इससे निवेश, रोजगार और संवृद्धि का एक सुचक्र शुरू करने में मदद मिलेगी।

9. 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान बाह्य मांग में उछाल आया और यह बढ़ते निर्यात, समग्र मांग को महत्वपूर्ण समर्थन देने में परिलक्षित हुआ। मजबूत बाह्य मांग भारत के लिए एक अवसर है और आगे नीतिगत समर्थन से इसे भुनाने में मदद मिलनी चाहिए। तथापि, वैश्विक पण्य कीमतों और वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव की घटनाएं, संक्रमण की नई लहरों के प्रति सुभेद्यता के साथ-साथ, आर्थिक गतिविधियों के लिए नकारात्मक जोखिम हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 2021-22 में 9.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है, जिसमें 2021-22 की पहली तिमाही में 21.4 प्रतिशत ; दूसरी तिमाही में 7.3 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 6.3 प्रतिशत; और चौथी तिमाही में 6.1 प्रतिशत शामिल हैं। 2022-23 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी विकास दर 17.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

मुद्रास्फीति

10. मई में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति तेजी से बढ़कर 6.3 प्रतिशत हो गई, जो प्रतिकूल आपूर्ति झटकों, क्षेत्र-विशिष्ट मांग-आपूर्ति बेमेल और बढ़ती वैश्विक पण्य कीमतों से स्पिलओवर पर सभी प्रमुख समूहों में वैविध्यपूर्ण बढ़ोत्तरी द्वारा संचालित थी। जून में यह 6.3 फीसदी पर रहा; हालांकि, कोर मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया।

11. दक्षिण-पश्चिम मानसून के पुनरुद्धार और खरीफ की बुवाई में तेजी, पर्याप्त खाद्य स्टॉक के बफर होने से आने वाले महीनों में अनाज की कीमतों के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। उच्च आवृत्ति वाले खाद्य मूल्य संकेतक सरकार द्वारा आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेप के कारण जुलाई में खाद्य तेलों और दालों की कीमतों में कुछ सौम्यता दिखाते हैं। मकान किराया जैसी प्रमुख सेवाओं में मुद्रास्फीति ऐतिहासिक औसत से नीचे बनी हुई है, जो कमजोर मांग की स्थिति को दर्शाती है। मुद्रास्फीति पर आयातित लागत दबावों के प्रभाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर हैं। औद्योगिक कच्चे माल की उंची कीमतों का संयोजन, पेट्रोल और डीजल की उच्च पंप कीमतें उनके दूसरे दौर के प्रभावों के साथ, और लॉजिस्टिक लागत, विनिर्माण और सेवाओं के लिए लागत की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, हालांकि कमजोर मांग की स्थिति उत्पादन मूल्य और मुख्य मुद्रास्फीति की पास-श्रू को प्रभावित कर रही है।

12. महामारी की शुरुआत से पहले, हेडलाइन मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति की उम्मीदें 4 प्रतिशत पर अच्छी तरह से टिकी हुई थीं, जिससे मिले लाभ को समेकित और संरक्षित करने की आवश्यकता है। मुद्रास्फीति दर में स्थिरता मौद्रिक नीति ढांचे की विश्वसनीयता को बढ़ावा देती है और मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को स्थिर करने के लिए शुभ संकेत देती है। यह बदले में, निवेशकों के लिए अनिश्चितता को कम

करता है, अवधि और जोखिम प्रीमियम को कम करता है, बाहरी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है और इस प्रकार, संवृद्धि को बढ़ावा देता है। महामारी की शुरुआत के बाद से, एमपीसी ने महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए संवृद्धि के पुनरुद्धार को प्राथमिकता दी है। उपलब्ध डेटा मुद्रास्फीति प्रक्रिया को चलाने वाले बहिर्जात और बड़े पैमाने पर अस्थायी आपूर्ति झटकों की ओर इशारा करता है, जो एमपीसी के निर्णय को मान्य करता है। आपूर्ति पक्ष के चालक क्षणभंगुर हो सकते हैं, जबकि अर्थव्यवस्था में सुस्ती को देखते हुए मांग दबाव निष्क्रिय बना रहता है। इस स्तर पर एक पूर्वकृत मौद्रिक नीति प्रतिक्रिया नवीन और संकोची बहाली को मार सकती है जो अत्यंत कठिन परिस्थितियों में पैर जमाने की कोशिश कर रही है।

13. मुद्रास्फीति 2021-22 की दूसरी तिमाही तक ऊपरी सहिष्णुता बैंड के करीब रह सकती है, लेकिन खरीफ फसल की आवक और आपूर्ति पक्ष के उपायों के प्रभावी होने के कारण इन दबावों को 2021-22 की तीसरी तिमाही में कम होना चाहिए। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2021-22 के दौरान सीपीआई मुद्रास्फीति अब 5.7 प्रतिशत पर अनुमानित है: 2021-22 की दूसरी तिमाही में 5.9 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 5.3 प्रतिशत; और चौथी तिमाही में 5.8 प्रतिशत, जिसमें जोखिम व्यापक रूप से संतुलित हैं। 2022-23 की पहली तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

चलनिधि और वित्तीय बाजार की स्थिति

14. जून-जुलाई के दौरान, कई देशों में उच्च मुद्रास्फीति संख्या और कुछ उन्नत देशों में विषम आर्थिक सुधार के साथ प्रारंभिक नीति सामान्यीकरण के डर के कारण वैश्विक वित्तीय बाजार अस्थिर हो गए। एक उपयुक्त प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए इन घटनाक्रमों को हमारी नीति मैट्रिक्स में शामिल करने की आवश्यकता है, यह देखते हुए कि वैश्विक स्पिलओवर के उलटफेर से अर्थव्यवस्था की रक्षा करना और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना रिज़र्व बैंक के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। फिर भी, घरेलू समष्टि आर्थिक स्थिति और विकसित होती मुद्रास्फीति गतिकी हमारी मौद्रिक नीति कार्रवाइयों की प्रमुख धुरी बनी रहेगी।

15. रिज़र्व बैंक ने अपने पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों तरह के बाजार परिचालनों के माध्यम से, घरेलू मांग के समर्थन में वित्तीय स्थितियों को आसान बनाने के लिए महामारी की शुरुआत के बाद से पर्याप्त अधिशेष चलनिधि बनाए रखी है। पूंजी प्रवाह की नई तेजी और द्वितीयक बाजार में रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद से उत्साहित, प्रतिवर्ती रेपो के माध्यम से कुल अवशोषण जून में दैनिक औसत के ₹5.7 लाख करोड़ से बढ़कर जुलाई 2021 में ₹6.8 लाख करोड़ और इसके अलावा अब तक अगस्त 2021 में (4 अगस्त तक) ₹8.5 लाख करोड़ हो गया।

16. [06 फरवरी 2020](#) को घोषित संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे के तहत, रिज़र्व बैंक अपने मुख्य चलनिधि परिचालन के रूप में 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित कर रहा है। सामान्य चलनिधि परिचालन की शुरुआत के साथ, वीआरआरआर, जिसे अस्थायी रूप से महामारी के दौरान रोक दिया गया था, को 15 जनवरी 2021 से फिर से आरंभ किया गया है और बाद की पाक्षिक नीलामी में ₹ 2 लाख करोड़ के प्रारंभिक अवशोषण को रोलओवर किया गया है। समानांतर में, स्थायी दर एक दिवसीय (ओवरनाइट) प्रतिवर्ती रेपो तक पहुंच को खुला रखा गया है। स्थायी दर एक दिवसीय प्रतिवर्ती रेपो के सापेक्ष इसके द्वारा ऑफर किए जाने वाले उच्च परिश्रमिक को ध्यान में रखते हुए बाजारों ने वीआरआरआर को अनुकूलित किया है और यहां तक कि इसका स्वागत भी किया है। आशंका है कि वीआरआरआर की शुरुआत चलनिधि की सख्ती के समान है, जिसे दूर कर दिया गया है। हमने

नीलामियों में बोली-रक्षा अनुपात के संदर्भ में वीआरआरआर के लिए अधिक रुचि देखी है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, अब 13 अगस्त 2021 को ₹2.5 लाख करोड़; 27 अगस्त 2021 को ₹3.0 लाख करोड़; 9 सितंबर 2021 को ₹3.5 लाख करोड़; और 24 सितंबर 2021 को ₹4.0 लाख करोड़ की पाक्षिक वीआरआरआर नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इन बढ़ी हुई वीआरआरआर नीलामियों को निभावकारी नीतिगत रुख के वापसी के रूप में नहीं पढा जाना चाहिए, क्योंकि स्थायी दर प्रतिवर्ती रेपो के तहत अवशोषित राशि सितंबर 2021 के अंत में ₹4.0 लाख करोड़ से अधिक रहने की उम्मीद है। यह जोड़ने की जरूरत नहीं है कि वीआरआरआर विंडो के तहत स्वीकृत राशि, प्रणाली चलनिधि का हिस्सा बनता है।

17. रिज़र्व बैंक का द्वितीयक बाजार जी-सेक अधिग्रहण कार्यक्रम (जी-एसएपी) बाजार सहभागियों से गहरी प्रतिक्रिया प्राप्त करते हुए प्रतिफल अपेक्षाओं को स्थिर करने में सफल रहा है। हम जी-एसएपी 2.0 के तहत 12 अगस्त और 26 अगस्त 2021 को ₹25,000 करोड़ की दो और नीलामी आयोजित करने का प्रस्ताव करते हैं। हम अन्य के साथ-साथ इन नीलामियों और अन्य कार्यों जैसे खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) और परिचालन ट्विस्ट (ओटी) को करना जारी रखेंगे, और उन्हें विकसित समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थितियों के अनुरूप कैलिब्रेट करेंगे।

18. इसके व्यवस्थित विकास के लिए प्रतिफल वक्र के सभी खंडों में सक्रिय व्यापार करना आवश्यक है। हमारी हालिया जी-एसएपी नीलामियों ने परिपक्वता अवधि में प्रतिभूतियों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिफल वक्र के सभी खंड तरल बने रहें। इसके अलावा, हमारे विकल्प जी-एसएपी नीलामियों और परिचालन ट्विस्ट में ऑफ द रन और ऑन रन प्रतिभूतियाँ दोनों को शामिल करने के लिए हमेशा खुले हैं। यह उम्मीद की जाती है कि द्वितीयक बाजार की मात्रा में वृद्धि होगी और बाजार सहभागियों ने ऐसी स्थिति बना ली है जिससे प्रतिफल में दोतरफा गति हो रही है।

19. केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के ऋण प्रबंधक के रूप में हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि रोलओवर जोखिम को कम करते हुए उचित लागत पर उनके उधार कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से पूरा किया जा सके। अपने पहले के भाषण में, मैंने सार्वजनिक वस्तु के रूप में प्रतिफल वक्र के क्रमिक विकास पर जोर दिया है जिसमें बाजार सहभागियों और रिज़र्व बैंक दोनों की साझा जिम्मेदारी है। चूंकि जी-सेक प्रतिफल एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है और ऋण बाजार के अन्य क्षेत्रों के लिए उच्च संकेत मूल्य है, प्राथमिक बाजार परिचालन में नीलामी कट-ऑफ, हस्तांतरण, रद्दीकरण और ग्रीन शू विकल्पों के प्रयोग के माध्यम से प्रतिफल के व्यवस्थित पथ पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया था। 14 साल की अवधि तक की प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए हाल ही में घोषित एकसमान मूल्य नीलामियों की शुरुआत से उन जोखिमों को कम करने की उम्मीद है जो बोली लगाने वालों को प्राथमिक खंड में सामना करना पड़ सकता है। मौजूदा नकद शेष के भीतर वर्ष की पहली छमाही के लिए राज्यों को जीएसटी मुआवजे के भुगतान को समायोजित करने के सरकार के निर्णय से इस वर्ष सरकार के उधार कार्यक्रम के आकार पर बाजार की चिंताओं को शांत करना चाहिए।

20. रिज़र्व बैंक के मौद्रिक नीति उपायों और कार्यों की प्रभावशीलता वर्तमान सहजता चक्र के दौरान संचरण में महत्वपूर्ण सुधार में परिलक्षित होती है। फरवरी 2019 से रेपो दर में 250 आधार अंकों की कमी के परिणामस्वरूप नए रुपये के ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) में 217 आधार अंकों की संचयी गिरावट आई है। कॉरपोरेट बॉन्ड, डिबेंचर, सीपी, सीडी और टी-बिल जैसे बाजार के साधनों पर ब्याज दरों सहित घरेलू उधारी लागत कम हुई है। ऋण बाजार में, एमएसएमई, आवास और बड़े उद्योगों के लिए उधार दरों का संचरण मजबूत हुआ है। कम ब्याज दर व्यवस्था ने घरेलू क्षेत्र को ऋण सेवा के बोझ को

कम करने में भी मदद की है। व्यक्तिगत आवास ऋण और वाणिज्यिक अचल संपत्ति क्षेत्र को ऋण पर ब्याज दरों में उल्लेखनीय कमी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि इन क्षेत्रों के पास व्यापक पिछला और आगे की सहलग्नता और गहन रोजगार हैं।

अतिरिक्त उपाय

21. महामारी की शुरुआत के बाद, रिज़र्व बैंक ने इसके प्रभाव को कम करने के लिए 100 से अधिक उपायों की घोषणा की है। आगे, हमारा प्रयास उन उपायों की निगरानी जारी रखना होगा जो अभी भी चल रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे सभी उपायों का लाभ लक्षित हितधारकों तक पहुंचे। इस पृष्ठभूमि में और व्यापक आर्थिक स्थिति और वित्तीय बाजार की स्थितियों के हमारे निरंतर मूल्यांकन के आधार पर, आज कुछ अतिरिक्त उपायों की घोषणा की जा रही है। इन उपायों का विवरण मौद्रिक नीति वक्तव्य के [विकासात्मक और विनियामक नीतियों \(भाग-बी\)](#) पर वक्तव्य में निर्धारित किया गया है। मैं इन उपायों के बारे में बताता हूँ।

ऑन टैप टीएलटीआरओ योजना – समय- सीमा का विस्तार

22. ऑन-टैप टीएलटीआरओ योजना का दायरा, शुरू में [9 अक्टूबर 2020](#) को पांच क्षेत्रों के लिए घोषित किया गया था, जिसे दिसंबर 2020 में कामथ समिति द्वारा पहचाने गए दवाबग्रस्त क्षेत्रों और फरवरी 2021 में एनबीएफसी को बैंक ऋण देने के लिए आगे बढ़ाया गया था। योजना की परिचालन अवधि को भी चरणों में 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाया गया था। नवजात और नाजुक आर्थिक सुधार को देखते हुए, अब ऑन-टैप टीएलटीआरओ योजना को तीन महीने की अवधि, अर्थात् 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) - छूट का बढ़ाया जाना

23. [27 मार्च 2020](#) को सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत बैंकों को सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में सकल मांग और समय देनदारियों (एनडीटीएल) में अतिरिक्त एक प्रतिशत तक अर्थात् संचयी रूप से एनडीटीएल के 3 प्रतिशत तक निधि का लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी। बैंकों को उनकी चलनिधि आवश्यकताओं पर सुलभता उपलब्ध कराने और उनकी चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह सुविधा जो 30 सितंबर 2021 तक उपलब्ध है, को तीन महीने की अतिरिक्त अवधि अर्थात् 31 दिसंबर 2021 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था ₹1.62 लाख करोड़ की सीमा तक धन की पहुंच प्रदान करती है और एलसीआर के लिए उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्ति (एचक्यूएलए) के रूप में पात्र है।

लिबोर पारगमन - दिशानिर्देशों की समीक्षा – विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण और डेरिवेटिव संविदाओं की पुनर्चना

24. लंदन अंतर- बैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) से पारगमन एक महत्वपूर्ण घटना है जो बैंकों और वित्तीय प्रणाली के लिए कुछ चुनौतियां पेश करती है। रिज़र्व बैंक सक्रिय रूप से कदम उठाने के लिए बैंकों और बाजार निकायों के साथ जुड़ रहा है। रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं और वित्तीय बाजारों के लिए भी एक सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सूचना जारी की है। इस संदर्भ में, (i) विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण और (ii) डेरिवेटिव संविदाओं की पुनर्चना से संबंधित दिशानिर्देशों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। बैंकों को संबंधित मुद्रा में किसी अन्य व्यापक रूप से स्वीकृत वैकल्पिक संदर्भ दर का उपयोग करके

विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण को प्रदान करने की अनुमति होगी। चूंकि लिबोर से संदर्भ दर में परिवर्तन एक "अप्रत्याशित घटना" है, बैंकों को सूचित किया जा रहा है कि संदर्भ दर में लिबोर /लिबोर-संबंधित बेंचमार्क से वैकल्पिक संदर्भ दर में परिवर्तन को पुनर्रचना नहीं माना जाएगा।

समाधान ढांचा 1.0 के तहत वित्तीय मानकों की उपलब्धि के लिए समय- सीमा को स्थगित करना

25. [6 अगस्त 2020 को घोषित कोविड-19 संबंधित दवाब के लिए समाधान ढांचा](#) के तहत लागू की गई समाधान योजनाओं को कई वित्तीय मापदंडों के संबंध में क्षेत्र विशिष्ट थ्रेसहोल्ड को पूरा करना आवश्यक है। इन मापदंडों में से, चार मापदंडों के संबंध में सीमाएं, उधार लेने वाली संस्थाओं के परिचालन निष्पादन से संबंधित हैं, अर्थात् ईबीआईडीटीए अनुपात की तुलना में कुल ऋण, वर्तमान अनुपात, ऋण सेवा कवरेज अनुपात और औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात। इन अनुपातों को 31 मार्च 2022 तक पूरा करने की आवश्यकता है। कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव और कारोबारों के पुनरुद्धार पर परिणामी कठिनाइयों को देखते हुए और परिचालन मापदंडों को पूरा करने के लिए, लक्ष्य तिथि को 1 अक्टूबर 2022 तक उपरोक्त चार मापदंडों के संबंध में निर्दिष्ट सीमाओं को पूरा करने के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

समापन टिप्पणी

26. जैसे-जैसे कोविड-19 की दूसरी लहर में कमी आती है, आशा है कि पर्याप्त महामारी प्रोटोकॉल और टीकाकरण दर में बढ़ोतरी के साथ, यदि तीसरी लहर आती है तो हम उसका सामना करने में सक्षम होंगे। एक राष्ट्र के रूप में, हमें अभी भी सतर्कता रखनी चाहिए और वायरस के अधिक तेजी से फैलने वाले म्यूटेंट के साथ महामारी के किसी भी पुनरुत्थान से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए, यदि अगर ऐसा हुआ।

27. बहाली सभी क्षेत्रों में असमान बनी हुई है और सभी नीति निर्माताओं द्वारा समर्थित होने की आवश्यकता है। रिज़र्व बैंक अपने सभी नीतिगत उत्तोलक - मौद्रिक, विवेकपूर्ण या विनियामक को तैनात करने के लिए तत्परता के साथ "चाहे जो भी हो" मोड में रहेगा। समानांतर में, वित्तीय स्थिरता के संरक्षण पर हमारा फोकस जारी है। इस समय, हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता यह है कि स्थिरता के साथ एक सतत संवृद्धि पथ सहित एक टिकाऊ बहाली सुनिश्चित करने के लिए विकास आवेगों का पोषण किया जाए। इस प्रयास में, हमने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर, सचेतन रूप से निराशा पर आशावाद को चुना है: "मैं एक अदम्य आशावादी हूं, लेकिन मैं हमेशा अपने आशावाद को ठोस तथ्यों पर आधारित रखता हूं"²।

धन्यवाद। सुरक्षित रहें। स्वस्थ रहें। नमस्कार।

(योगेश दयाल)

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/643

मुख्य महाप्रबंधक

² स्रोत: पुस्तक "महात्मा" द्वारा डी.जी तेंदुलकर, वॉल्यूम 2